स्वास्थ्य क्षेत्र में अब निजी भागीदारी बढ़ाने की तैयारी

■ राजकुमार शर्मा

लखनऊ। यूपी में हेल्थ सेक्टर में प्रदेश सरकार निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने की तैयारी में है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के लोग सरकार की मदद से अस्पताल स्थापित कर सकेंगे। इसमें योजना क्षेत्रों के हिसाब से अलग-अलग तरह की रियायतें देने की हैं। मसलन बड़े और प्रमुख शहरों में अस्पताल के लिए ली जाने वाली जमीन पर सरकार स्टांप ड्यूटी माफ किए जाने पर विचार कर रही है। वहीं मध्यम श्रेणी के शहरों में जमीन खरीद पर छूट मिल सकती है जबकि पिछड़े जिलों में अस्पताल खोलने की इच्छुक कंपनियों को मुफ्त जमीन दी जा सकती है।

योगी सरकार की योजना सबको घर के नजदीक स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने की है। इसके लिए कई तरह की पहल की गई हैं। स्वास्थ्य उपकेंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के रूप में अपग्रेड किया गया है। पीएचसी और सीएचसी पर सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। अब सरकार की मंशा स्वास्थ्य सेक्टर के द्वार निजी क्षेत्र के लिए खोले जाने की है। इसके लिए नई नीति लाने की तैयारी है।

पिछड़े इलाकों पर सरकार का जोर

सरकार अच्छे और अत्याधुनिक विशेषताओं और सुविधाओं से युक्त अस्पताल बनाने के लिए निजी क्षेत्र के लोगों को आमंत्रित करेगी। उन्हें जरूरत और क्षेत्र के हिसाब से सुविधाएं दी जाएंगी। सबसे ज्यादा फोकस बुंदेलखंड सहित उन इलाकों में है, जहां स्वास्थ्य सेवाएं अपेक्षाकृत कम हैं। वहां निजी निवेशकों को मुफ्त जमीन दिए जाने पर विचार हो रहा है।